

दवा पीएसयू के पुनरुद्धार पर फैसला अटका

बिजनेस भास्कर ▶ नई दिल्ली...

सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों के पुनरुद्धार पर बड़ी पहल अब नई सरकार ही कर सकेगी। आगामी आम चुनाव के मद्देनजर अगले माह लागू हो रही अधिसूचना को देखते हुए दवा पीएसयू इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (आईडीपीएल) के लिए पैकेज को मंजूरी मिलना मुश्किल लग रहा है।

डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आईडीपीएल के लिए पैकेज

के प्रस्ताव पर फैसला मार्च के पहले होना कठिन है। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना लागू होनी है। आईडीपीएल के पुनरुद्धार के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये का पैकेज तैयार किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल आईडीपीएल के अलावा और कई बीमार पीएसयू का उत्पादन बढ़ाने और उनको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की योजना पर काम कर रहा था। केंद्र सरकार ने कुछ माह पहले पीएसयू दवा कंपनियों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी को नए सिरे से लागू

किया है। पॉलिसी के तहत दवा पीएसयू को 103 जेनरिक दवाओं का निर्माण करना है। पीएसयू दवा कंपनियों के पूरी क्षमता के साथ काम न कर पाने के कारण केंद्र सरकार की जन औषधि योजना को भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सका। जन औषधि योजना दवा पीएसयू की लचर दवा आपूर्ति के कारण फ्लाप साबित हुई है। नए बिजनेस प्लान में जन औषधि स्कीम में दवा आपूर्ति के लिए पीएसयू दवा कंपनियों के साथ निजी दवा कंपनियों को भी शामिल किया गया है।